पहुंच सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ना

3173. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक गांव को पहुंच सड़क द्वारा जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनको अब तक पहुंच सड़क के साथ जोड़ दिया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) से (ग) सभी श्रेणी के गांवों को संपर्क सड़कों से जोड़ना राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें ने अपनी वार्षिक योजना में निधियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) 1000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले उन गांवों, जिन्हें संपर्क सड़कों से जोड़ा जा चुका है, की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बारहमासी सड़कों के साथ 1000 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या को जोड़ना

	राज्य	गांवों की कुल संख्या	1995-96 तक सड़कों से जुड़े गांवों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13467	11647
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	71
3.	असम	3719	3719
4.	बिहार	14332	9359
5.	गोवा	226	201
6.	गुजरात	8300	8292
7.	हरियाणा	3470	3468
8.	हिमाचल प्रदेश	459	450
9.	जम्मू और कश्मीर	1178	1035
10.	कर्नाटक	8396	6915
11.	केरल	1262	1262
12.	मध्य प्रदेश	7337	5742
13.	महाराष्ट्र	11328	11162
14.	मणिपुर	277	268
15.	मेघालय	109	109
16.	मिजोरम	342	342
17.	नागालैंड	240	240
18.	उड़ीसा	6173	5811
19.	पंजाब	3346	3346
20.	राजस्थान	5707	5280
21.	सिक्किम	69	64
22.	तमिलनाडु	6432	6424
23.	त्रिपुरा	535	535
24.	उत्तर प्रदेश	22295	18529
25.	पश्चिम बंगाल	10428	6705
26.	अंडमान और निकोबार	31	31
27.	चंडीगढ़	16	16
28.	दादरा और नागर हवेली	38	38
29.	दमन और दीव	15	15
30.	दिल्ली	160	160
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	84	84
		344	344
		129852	111320

National Mission for Housing

3174. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that 66 per cent of the total housing shortage in the country is in the rural areas;

(b) whether Government have so far finalised the proposal for setting up a Naitonal Mission in this regard; and

(c) if so, the details thereof indicating the targets set for additional housing units/allocation of funds etc. during 1998-99 particularly in respect of Rajasthan State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) In view of reply to (b) above, question does not aries.

Raising of Funds for ARWSP, IRDP & IAY

3175. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT bc pleased to state:

(a) whether Government propose to raise allocation of funds for the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) as well as for Integrated Rural Development Programme and Indira Awas Yojana Schemes in respect of the States of Rajasthan and Orissa during 1998-99; and

(b) if so, the details thereof indicating the increase in funds for 1998-99 year, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) In the Budget of the Ministry for 1998-99, there is a proposal to raise allocation of funds for Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), Integrated Rural Development Programme (IRDP) and Indira Awas Yojana (IAY). State-wise allocations would be based on the approval by the Parliament of the Budget for the year 1998-99.

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान में बनाई जाने वाली रिहायशी इकाइयां

3176. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "इंदिरा आवास योजना" के अंतर्गत रिहायशी इकाइयों के निर्माण के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितनी रिहायशी इकाइयां उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितनी रिहायशी इकाइयां बनाई जायेंगी और इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) से (ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ति

3177. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य ऐसे कार्यक्रमों से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने गरीबी उन्मूलन में इन कार्यक्रमों की सफलता के आकलन के लिए कोई अध्ययन करवाया है; यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) वर्ष 1980 में शुरुआत होने से लेकर अब तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 527.14 लाख परिवारों को सहायता दी गई है।

(ख) आरम्भ से लेकर अब तक कुल 10532.23 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है और 20372.00 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है।